VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M
N
02 NOV 2016
No. 3
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 843)

Name of Candidate	KANCHAN KUMAR KANDPAL		
Medium Hindi/Eng.	HINDI	Registration Number	26216
Center	MN	Date	2/11/2015

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

All the questions are compulsory and carry 12.5 marks each.

1. Discuss the need for adhering to the road map for fiscal consolidation by fixing the fiscal deficit. Has the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 served the purpose for which it was envisaged?

राजकोषीय घाटा के निर्धारण के माध्यम से राजकोषीय समेकन (कंसोलिडेशन) के लिए एक रोड मैप का पालन करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। क्या राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम) अधिनियम, 2003 ने अपनी परिकल्पना के उद्देश्य की पूर्ति की है?

किसी सरकार के आय व व्यय के मध्य का अन्तर उसका राजकोषीय घाटा कहलाता है, चूँकि विकासशील देशों मे विकासकार्यों हेतु सार्वजनिक व्यय की अत्यधिक आवश्यकता होती है, साथ ही कल्याणकारी नीतियों, सब्सिडी आदि के कारण भी सरकार के वित्तीय दायित्व में वृद्धि होती है, परिणामत: सरकार के राजकोषीय घाटे में निरंतर वृद्धि होती है, जो न केवल अर्थव्यवस्था अपितु सरकार के बजट प्रबंधन की दृष्टि से नकारात्मक संकेत है,

राजकोषीय घाटे को कम कर समान्वित स्तर तक लाने की प्रक्रिया ही राजकोषीय समेकन कहलाती है। सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को निर्धारित कर, राजकोषीय समेकन हेतु

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रयत्न किये जाते हैं, वस्तुतः ऐसा रोडमैप
(i) सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने,
(ii) गैर उत्पादक गतिविधियों को नियंत्रित करने
(iii) सरकार के अनावश्यक व्यय में रोक लगाने
के लिए नितांत लाभकारी सिद्ध होता है, यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित न कर राजकोषीय घाटे की यथास्थिति बनी रहने दी जाएगी, तो यह भविष्य में आर्थिक संवृद्धि व विकास के मार्ग में बाधा बनेगा,

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम – 2003 का मूल्यांकन:

(i) यह अधिनियम 2003 में पारित किया गया था, जिसमें 2008 तक राजस्व घाटे को शून्य तथा राजकोषीय घाटे को 3% तक लाने का उद्देश्य रखा गया था,
(ii) 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के भारत पर पड़े प्रभाव के कारण

इसके लक्ष्यों को भविष्य हेतु स्थानांतरित कर दिया गया,

(iii) वर्तमान में (2015-16) में राजकोषीय घाटे की स्थिति में सुधार तथा भविष्य के लिए 3.6% के लक्ष्य का निर्धारण इस अधिनियम के सकारात्मक प्रभावों को दिखाता है।

(iv) वर्तमान में गैर उत्पादक योजनाओं के बजट में कटौति, गिव इट अप, लक्षित सब्सिडी हस्तांतरण जैसी योजनाएँ इसके भविष्यगामी लक्ष्यों की तरफ उन्मुख हैं।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Public investment in railways has a multiplier effect for the larger economy. Elaborate. What factors have held back the railways despite having a separate budget and considerable resources? In this context, enumerate the relevant recommendations of Bibek Debroy committee?

रेलवे में किए गए सार्वजनिक निवेश का, वृहद् अर्थव्यवस्था के लिए गुणक (मल्टीप्लायर) प्रभाव होता है। विस्तार पूर्वक बताईए। अलग बजट और यथेष्ट संसाधनों के बावजूद कौन से कारकों ने रेलवे को पीछे रखा है? इस संदर्भ में, बिबेक देबरॉय समिति की प्रासंगिक अनुशंसाएं बताईए?

रेलवे, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता है, न केवल एक यात्रा साधन के रूप में, बल्कि अन्य क्षेत्रों की रेलवे पर निर्भरता के कारण यह अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव रखता है। जिसे इन बिन्दुओं के द्वारा समझा जा सकता है :-

(1). प्रतिदिन करोड़ो यात्री, इसके माध्यम से ही यात्रा करते हैं,

(2). सर्वाधिक कर्मचारी वर्ग,

(3). माल एवं वस्तुओं के स्थानान्तरण का सर्वाधिक बड़ा माध्यम,

(4). क्षेत्रीय एकीकरण का माध्यम

(5). पर्यटन हेतु प्रयोग किया जाने वाला सबसे प्रमुख यात्रा साधन,

रेलवे के विकास में अवरोधक :

(1) रेलवे के यात्री किरायों का राजनीति

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

से प्रेरित होने के कारण लागत से कम होना।

(ii). भारतीय रेल में केवल 3rd AC (तृतीय श्रेणी वातानुकूलित डब्बा) ही लागत को वसूल पाता है।

(iii). रेलवे कर्मचारियों हेतु स्कूल, आवास आदि अनावश्यक व्यय,

(iv). देश की भौगोलिक विषमता के कारण पर्याप्त विस्तार का अभाव,

(v). रेलवे बजट को प्रदर्शन आधारित के बजाय लोकलुभावन बनाना

बिबेक देवराय समिति की अनुशंसाएँ

(i) अप्रासंगिक हो चुके अलग रेल बजट के प्रावधान को समाप्त किया जाए,

(ii) रेलवे में बिजनेस अकाउंट बजटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए,

(iii) भावनात्मक घोषणाओं से दूर रहा जाए,

(iv) यात्री किराया दरों को लागत

अनुकूल बनाया जाए।

(v) रेलवे कर्मचारियों हेतु संचालित स्कूल, अस्पताल, आवास आदि के अनावश्यक बोझ को दूर किया जाए।

निष्कर्ष- रेलवे के विकास स्तर को विश्व मानकों के अनुरूप बनाने हेतु समय आ गया है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति युक्त कठोर कदम उठाए जाएँ, ताकि रेलवे अधिक दक्ष व प्रभावकारी बन सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. "There is a myth that small firms create the most jobs in an economy. The fact is that small firms that grow big create the jobs". In context of the Indian economy what are the factors that prevent firms that start small from growing bigger. What progress has India made in this respect and what other measures are required?

"ऐसा मिथक है कि किसी अर्थव्यवस्था में छोटी फर्में सर्वाधिक रोजगार पैदा करती हैं। जबकि तथ्य यह है कि वही छोटी फर्में जो बड़ी फर्मों के रूप में विकसित होती हैं, रोजगार पैदा करती हैं"। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, छोटी फर्मों को बड़ी फर्मों के रूप में विकसित होने से रोकने वाले कारक कौन-से हैं? इस संदर्भ में भारत ने क्या प्रगति की है और कौन-से अन्य उपाय आवश्यक हैं?

किसी अर्थव्यवस्था के विकासक्रम में छोटी फर्मों का बड़ी फर्मों के रूप में परिवर्तन होता है, और रोजगार के अवसरों में इसके प्रभाव से वृद्धि होती है, परंपरागत रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता होते हैं, किंतु यह तथ्य भी प्रासंगिक है कि इनके विकास होने पर ही ये बड़े नियोक्ता वर्ग को धारण कर पाने में सक्षम हो पाएंगे,

भारत में छोटी फर्मों के विकास की स्थिति -

① आर्थिक सर्वेक्षण - 2016 में इस तथ्य को मुक्त कंठ से स्वीकृत किया गया है कि भारत में व विकसित देश में समान समय में खुले छोटे उद्योगों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

में से भारतीय उद्योग बेहद धीमी गति से वृद्धि कर पाते हैं;

(ii) कड़े श्रम कानून व इंस्पेक्टर राज विकास की गति को धीमा करते हैं,

(iii) उद्योग विस्तार हेतु पूंजी का अभाव,

(iv) उत्पाद वितरण श्रृंखला का प्रभावी व सक्षम न होना,

(v) पर्यावरण मानकों की कठोर,

(vi) श्रमिक हड़तालें,

(vii) उद्योग विस्तार हेतु प्रोत्साहन का अभाव,

भारत की प्रगति -

(i) श्रमेव जयते कार्यक्रम द्वारा श्रम नियमों को औद्योगिक विकास हितैषी बनाया गया है,

(ii) पर्यावरण मानकों की अनावश्यक बाधा को दूर किया गया है,

(iii) मेक-इन इंडिया अभियान द्वारा औद्योगिक विस्तार व विकास को बढ़ावा,

(iv) पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हेतु बैंक ऋण तक आसान पहुँच,

(V) यह भारत की प्रगति का ही सूचक है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक में हमारा स्थान 39 वाँ हो गया है।

अन्य अपेक्षित उपाय-

(I) दिवालियापन कानून को अधिक प्रगतिशील बनाया जाए, ताकि रुग्ण इकाईयाँ प्रतिस्पर्द्धा पर अनावश्यक दबाव न डालें।

(II) स्टार्ट-अप इण्डिया को संपोषणीय सहयोग, ताकि इसके अंतर्गत खुले उद्योग विस्तार पा सके,

(III) पूँजी की सुलभता को प्रभावी बनाया जाए,

(IV) भू-अधिग्रहण कानून को उद्योग हितैषी बनाया जाए।

4. Enumerate the reasons why problem of NPAs is more pronounced in the public sector banks as compared to the private sector. Discuss the implications of having high NPAs in an economy. Also list the measures which the government has taken in order to address them.

निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एन.पी.ए. की समस्या अधिक गंभीर होने के कारण बताएं। किसी अर्थव्यवस्था में उच्च एन.पी.ए. के निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाये गए कदमों को भी सूचीबद्ध कीजिए।

बैंक को जिस ऋण से ब्याज/ऋण की प्राप्ति 91 से अधिक दिनों से नहीं होती है, उसे एन० पी० ए० के रूप में वर्गीकृत किया जाता है,

सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक एन०पी० ए० -

(i) ऋण वसूली प्रबंधन तंत्र का प्रभावी न होना,

(ii) ऋणी (Borrower) व्यक्ति की गतिविधि (बिजनेस मॉडल आदि) की समग्र निगरानी के प्रति उदासीनता,

(iii) निजी बैंक अपने कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन आधारित प्रोन्नति/वेतन का प्रावधान रखते हैं, जो बेहतर निगरानी हेतु उन्हें प्रेरित करता है।

(iv) सार्वजनिक बैंकों में उच्च अधिकारी वर्ग के प्रति जवाबदेहिता की समुचित

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संस्कृति का अभाव,

(v) अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भावनात्मक आधार पर ऋण देते हैं, न कि पुराने रिकार्ड को देखकर,

(vi) राजनीतिक लाभ के कारण सरकारी बैंकों को दण्डात्मक कार्यवाही से रोका जाता है,

एन० पी० ए० का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

(i) अनुत्पादक पूंजी को बढ़ावा,

(ii) उत्पादक कार्यों - औद्योगिक विकास, कल्याणकारी योजना आदि के लिए पूंजी का अभाव,

(iii) उपभोक्ता (ऋणी) वर्ग को ऋण अदायगी के लिए नकारात्मक रूप से प्रभावित करना, जो कि विकृत आर्थिक संस्कृति को जन्म देता है,

(iv) बैंकों की बैलेंस शीट का खराब (Red) हो जाना,

(v) पूंजी अभाव के कारण आर्थिक विकास का रुक जाना,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकार द्वारा प्रयत्न-

(i) बैंकों को अपनी बैलेंसी शीट को पुनर्गठित करने हेतु निर्देशित करना।

(ii) सभी ऋणों को सूचीबद्ध (High Risk, Stressed, N.P.A.) करना,

(iii) विलफुल डिफॉल्टर ऋणियों पर दबाव बनाना,

(iv) बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन,

(v) बैड बैंक की स्थापना के प्रयत्न।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Mention the salient features of the Hybrid Annuity Model (HAM) proposed by the government to reinvigorate private investment in infrastructure sector. How is it an improvement over the EPC model?

अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश को पुनर्जीवित करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एच.ए.एम.) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कैसे यह ई.पी.सी. मॉडल से बेहतर सुधार(इम्प्रूवमेंट) है?

अवसंरचना क्षेत्र में भारी निवेश की पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग आवश्यक है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सरकार ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) को प्रस्तावित किया है,

विशेषताएँ -

(i) प्रारंभ में सरकार द्वारा 40% राशि को निवेश किया जाएगा,

(ii) शेष राशि निजी निवेशकों द्वारा अगले वर्षों में लगाई जाएगी,

(iii) निर्माण हो जाने के बाद टोल से प्राप्त राशि के जरिए सरकार निवेशकों को भुगतान करेगी,

(iv) निवेशित राशि में सरकार व निजी क्षेत्र के विभिन्न अंशदान को ही 'हाइब्रिड' कहा जाता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ई० पी० सी० मॉडल से बेहतर क्यों?

(i) सरकार द्वारा प्रारंभिक 40% का भुगतान होने के कारण निजी निवेशकों में HAM मॉडल के प्रति अधिक भरोसा।

(ii) ई० पी० सी० मॉडल में इंजीनियरिंग दोषों का उत्तरदायित्व निजी निवेशक पर होने के कारण उदासीनता,

(iii) टोल आधारित भुगतान होने के कारण यह सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं डालेगी,

निष्कर्ष - अवसंरचनात्मक क्षेत्र में आर गतिहीनता को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र को निवेश हेतु प्रेरित करना आवश्यक है, HAM मॉडल इस दिशा में सकारात्मक कदम साबित होगा,

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Even within the multilateral format of WTO the FTA route has served India well. Comment. How can India effectively deal with the challenges posed by the new mega regional agreements such as TPP?

यहां तक कि डब्लू.टी.ओ. के बहुपक्षीय प्रारूप (multilateral format) के अंतर्गत भी भारत को एफ.टी.ए. मार्ग (FTA route) का अच्छा साथ मिला है। टिप्पणी कीजिए। भारत टी.पी.पी. जैसे नये मेगा क्षेत्रीय समझौतों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से किस प्रकार प्रभावी ढंग से निपट सकता है?

(i) WTO के विदेशी व्यापार संबंधी मॉडल के बहुपक्षीय प्रारूप के अंतर्गत सभी सदस्य राष्ट्र व्यापार वृद्धि के लिए अधिकतम खुलेपन की नीति अपनाते हैं।

(ii) किंतु सभी सदस्यों द्वारा नियमों का 100 % अनुपालन न होने के कारण सदस्य राष्ट्र मुक्त व्यापार समझौतों की तरफ बढ़ते हैं।

(iii) भारत ने भी FTA द्वारा व्यापार वृद्धि के अनेक प्रयास किए हैं, जिसमें

1. सार्क
2. श्रीलंका

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. दक्षिण कोरिया
प्रमुख है,

(iv) FTA द्वारा भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना निर्यात आधार स्थापित करने में सफल हुआ है

(v) FTA सदस्यों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों से भारतीय उपभोक्ता वर्ग भी लाभान्वित हुआ है

नए समझौते की चुनौती से बचाव

(1) नए समझौते संबंधित सदस्यों को ही मुक्त व्यापार का लाभ देंगे। अर्थात भारत को नुकसान होगा

- भारत के हस्तशिल्प निर्यात में कमी
- वियतनाम, इंडोनेशिया से प्रतिस्पर्धा द्वारा लकड़ी निर्यात में कमी
- श्रम निर्यात में बाधा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ii) अतः भारत को रणनीतिगत रूप से FTA के लिए अधिकांश देशों से संपर्क करना होगा।

(iii) अफ्रीका, EU जैसे राष्ट्रों पर फोकस कर भारत बेहतर व्यापारिक / आर्थिक लाभ कमा सकता है।

(iv) Act East व Bonding with west को सशक्त हथियार बनाना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Cashless economy is a global trend now. What are the challenges of achieving a cashless economy in the case of India? How can these challenges be overcome?

नकदीरहित (कैशलेस) अर्थव्यवस्था अब वैश्विक प्रवृत्ति बन गई है। भारत के प्रकरण में नकदीरहित अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियां क्या हैं? इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समस्त वित्तीय लेन-देन इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्पन्न हों, नकदी रहित अर्थव्यवस्था कहलाता है,

वैश्विक स्तर पर नकदी रहित प्रणाली

(i) स्वीडन, डेनमार्क जैसे देश 100% नकदीरहित अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर चुके हैं,

(ii) विकसित राष्ट्रों में बढ़ती ऑनलाइन व्यापार की प्रक्रिया, क्रेडिट, डेबिट कार्ड का 90% से अधिक प्रयोग,

(iii) विकासशील देशों भारत, कीनिया आदि में एम. मनी (Mobile Money) को प्रेरित करने वाले सरकारी प्रयास,

भारत के समक्ष चुनौतियाँ -

(i) वृहद् जनसंख्या का डिजीटल हस्तांतरण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की जानकारी से अवगत कराना,

(ii) इंटरनेट के सभी लोगों तक पहुँचे बिना यह कार्य असंभव,

(iii) परंपरागत व्यवसायी वर्ग को नवीन प्रक्रिया के लिए प्रेरित करना,

(iv) काला धन की प्रचुरता (समांतर अर्थव्यवस्था) को बनाए रखने के आकांक्षी समूह का प्रतिरोध

(v) अधिकतम (80% +) आर्थिक गतिविधियों का तकनीक रहित रिटेल (खुदरा) दुकानों पर संपादन,

समाधान के उपाय -

(i) बजट - 2016 में 1 लाख से अधिक के नकदी हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने जैसे प्रस्तावों को शीघ्र लागू करना,

(ii) क्रेडिट, डेबिट, रूपे कार्ड को बहुआयामी बनाकर इनके उपयोग को बढ़ावा,

(iii) ऑनलाइन हस्तांतरण को प्रभावी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बनाने हेतु इंटरनेट के प्रसार के प्रयास,

(iv) बसों, ट्रेन, मेट्रो में यात्रियों को नकद के बजाय कार्ड आधारित भुगतान हेतु प्रेरित करना,

(v) यह उपाय तभी संभव हो पाएँगे, जब सभी का वित्तीय समावेशन संभव होगा, अतः जन-धन जैसी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Abysmal level of formally skilled workers in Indian economy, as indicated by the Labour Bureau Report 2014, is a cause of concern. What are the factors responsible for such a scenario? Also, examine the measures taken by the government in recent years to address the relevant concerns.

श्रम ब्यूरो रिपोर्ट 2014 द्वारा यथा इंगित, भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों का अति निम्न (Abysmal) स्तर, चिंता का कारण है। ऐसे परिदृश्य के लिए उत्तरदायी कारक कौन-से हैं? साथ ही, प्रासंगिक चिंताओं को दूर करने हेतु हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए।

श्रम ब्यूरो रिपोर्ट - 2014 ने दो तिहाई से अधिक श्रम बल को कुशलता के औपचारिक स्तर से नीचे बताया, साथ ही नए तैयार हो रहे इंजीनियर, प्रबंधक छात्रों को भी वैश्विक मानकों से काफी पीछे बताया,

श्रमिक अकुशलता के उत्तरदायी कारण

(I) तकनीकी शिक्षा का अभाव,

(II) ऐसे श्रम गहन उद्योगों की उपस्थिति जिसमें कौशल की अपेक्षा श्रम का महत्व था,

(III) सूक्ष्म व मझोले उद्योगों के विकास का अभाव,

(IV) उत्तर भारतीय राज्यों में तकनीकि शिक्षा के सापेक्ष परंपरागत विषयों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को ही अध्ययन का विषय बनाना,

(v) कौशल विकास कार्यक्रमों का अभाव

(vi) औद्योगिक श्रम के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण,

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन -

(i) कौशल विकास योजना के अनेक कार्यक्रम

- दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना
- रोशनी योजना
- नई मंजिल

को प्रारंभ किया गया है, ये निश्चित रूप से बड़ी संख्या में श्रमिकों को कुशल बनाएँगे,

(ii) उस्ताद योजना आदि के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्प कौशल को बढ़ावा देना, प्रभावी कदम है,

(iii) औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को पुनर्संरचित करना भी गुणात्मक सुधार लाएगा,

(iv) तकनीकी शिक्षा के उन्नयन के प्रयत्न भी भविष्य में लाभान्वित करेंगे।

निष्कर्ष - स्पष्टतः कौशल विकास वर्तमान की आवश्यकता व भविष्य की नींव है, सरकार द्वारा वर्तमान में उठाए गए कदम निश्चित रूप से समृद्ध भारत को सिद्ध करेंगे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. In the 10 years of its existence MGNREGA has won laurels as well as attracted criticism. Comment. What changes are required for the scheme to be relevant in the current scenario.

अपने अस्तित्व के 10 वर्षों में मनरेगा ने ख्याति अर्जन के साथ ही आलोचनाएं भी झेली है। टिप्पणी कीजिए। वर्तमान परिदृश्य में योजना को प्रासंगिक बनाने के लिए कौन से परिवर्तनों की आवश्यकता है?

रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में प्रारंभ किया गया मनरेगा अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में कल्याणकारी राज्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ है।

(i) 33% से अधिक महिला कामगारों को रोजगार,

(ii) 20% से अधिक SC/ST/OBC वर्ग को रोजगार देकर सशक्त बनाया है।

(iii) ग्रामीण अवसंरचना सुधार का प्रभावी माध्यम

(iv) न्यूनतम मजदूरी की दर को बढ़ाकर श्रमिक वर्ग को सशक्त बनाया है,

(v) अनावश्यक शहरी पलायन में कमी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आलोचनाएँ -

(i) गैर उत्पादक कार्यों की तरफ झुकाव,

(ii) मनरेगा श्रमिकों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं देता,

(iii) पेरोल, श्रमिक वेतन भुगतान में भ्रष्टाचार की शिकायतें

(iv) ग्रामीण मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी बेरोजगार वर्ग को कुप्रभावित करती है,

(v) अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाने में असक्षम,

(vi) इसके प्रवर्तक जीन द्रेजे ने स्वयं इसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर संदेह व्यक्त किया है,

परिवर्तनों हेतु सुझाव-

(i) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिन तालाबों, कुओं के निर्माण की बात की गई है,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

से मनरेगा से जोड़ा जाए।

(ii) जैविक कृषि हेतु कंपोस्ट बनाने जैसे कार्यों को इससे संबद्ध किया जाए।

(iii) डीबीटी आधारित भुगतान को अधिक सशक्त बनाया जाए।

(iv) वंचित वर्ग के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर जोर दिया जाए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Power sector reforms, crucial as they are, have remained elusive. Discuss the reasons for their failure. How far can the UDAY scheme address the issues concerning DISCOMS and improve the entire power sector value chain?

बिजली क्षेत्र में सुधार अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के बावजूद दुष्प्राप्य बने हुए हैं। इनकी विफलता के कारणों पर चर्चा कीजिए। उदय (UDAY) योजना डिस्कॉम (DISCOMS) से संबंधित समस्याओं को किस सीमा तक समाधान कर सकती है और समस्त विद्युत क्षेत्रक मूल्य श्रृंखला(power sector value chain) में कैसे सुधार ला सकती है?

वर्तमान अर्थव्यवस्था के विकास में विद्युत की अति-महत्वपूर्ण संचालक भूमिका होती है, साथ ही यह आर्थिक-सामाजिक विकास की भी सूचक है, महत्व के बावजूद बिजली क्षेत्र में सुधार आज भी दुष्प्राप्य है।

प्रमुख कारण –

(I). राज्य सूची का विषय होने के कारण आज भारत में बिजली के 29 अलग-अलग बाजार हैं;

(II) बिजली चोरी जैसी समस्याएँ अभी भी जारी हैं;

(III) इलेक्ट्रॉनिक मीटर जैसे तकनीकि उपाय अधूरे हैं;

(IV) वितरण हानियों को कम करने हेतु उपयुक्त तकनीकों का अभाव

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(v) बिजली मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडी का राजनीति प्रेरित होना,

(vi) सब्सिडी प्राप्त बिजली का अनावश्यक /व्यर्थ उपयोग

(vii) एक देश - एक ग्रिड के स्वप्न का अभी भी अधूरा होना,

उदय योजना की भूमिका

(i) यह वितरण कंपनियों के हानियों (ऋण) के निराकरण हेतु बनाई गई योजना है,

(ii) वितरण कंपनियों को ऋणमुक्त करना AT&D हानियों को कम करने के लिए प्रेरित करेगी,

(iii) वितरण कंपनियों के ऋण को नॉन - एसएलआर बाण्ड के रूप में प्रयोग की अनुमति,

(iv) अंततः यह पावरिंग इंडिया के उद्देश्य के साथ एकीकृत मूल्य व्यवस्था लाने में सक्षम सिद्ध होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्टतः उपर्युक्त प्रयत्न न केवल वैद्युत क्षेत्रक सुधार को प्रभावी बनाएँगे बल्कि मूल्य श्रृंखला में भी सुधार लाएगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Market volatility and vulnerability to weather are the major issues facing Indian agriculture. Elaborate. In this regard, critically examine the importance of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana vis-a-vis earlier insurance schemes in addressing the problems of Indian agriculture.

बाजार की अस्थिरता और मौसम के प्रति सुभेद्यता (vulnerability to weather) भारतीय कृषि के समक्ष बड़ी समस्याएं हैं। वर्णन कीजिए। इस संबंध में भारतीय कृषि की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में पूर्व की बीमा योजनाओं की तुलना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

भारत के लगभग २५ करोड़ परिवार कृषि पर आश्रित हैं, तथा कृषि प्रधान भारत में कृषि व्यवस्था वस्तुतः बाजार व मौसम की गतिविधियों के प्रति सुभेद्य है।

(i) लगभग 55% भारतीय कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए मानसून आश्रित है।

(ii) सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान,

(iii) बाजार मूल्यों की अस्थिरता के कारण आय के प्रति अनिश्चितता,

(iv) बिचौलिया का प्रभाव अधिक होने के कारण लागत वसूली नहीं,

(v) अति उत्पादन के कारण फसल

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मूल्य में गिरावट,

(vi) कृषि अनाज मंडियों के एकाधिकार के कारण वास्तविक लाभ से वंचन।

(vii) उपर्युक्त कारणों के सम्मिलित प्रभाव से कृषक वर्ग आज आत्महत्या, गरीबी, भुखमरी व अल्प लाभ की समस्या के कुचक्र में फंसा है।

नई फसल बीमा योजना की श्रेष्ठता

(i) इसमें वाणिज्यिक व बागवानी फसलों को भी समाहित किया गया है।

(ii) अलग-अलग फसल श्रेणियों के लिए विभेदित बीमा दरें,

(iii) फसल कटाई के 14 दिन बाद तक का बीमा कवर,

(iv) ओलावृष्टि, अतिवृष्टि को भी आपदा के रूप में स्वीकृति,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(v) किंतु जंगली जानवरों के द्वारा हुए नुकसान को बीमा कवर नहीं,

(vi) जागरुकता के अभाव में योजना की असफलता की संभावना,

(vii) राज्यों को सीमित राशि में हिस्सेदारी के लिए (50:50) प्रेरित करना चुनौती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. The Hydrocarbon Exploration Licensing Policy (HELP) is a step forward from the New Exploration Licensing Policy (NELP). Compare the two policies and elaborate how HELP can encourage investment in the hydrocarbon sector as well as curtail India's export dependence?

हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन (अन्वेषण) लाइसेंसिंग पॉलिसी (नीति) [HELP], न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (NELP) से एक कदम आगे है। दोनों नीतियों की तुलना कीजिए और वर्णन कीजिए कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ ही आयात पर भारत की निर्भरता कम करने में HELP किस प्रकार सहायता प्रदान सकता है?

NELP	HELP
1. प्रत्येक हाइड्रोकार्बन के लिए अलग लाइसेंस	एक ही लाइसेंस द्वारा सभी हाइड्रोकार्बन का उत्खनन
2. लाभ वितरण समझौता पर आधारित।	रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर आधारित
3. सामुदायिक उत्तरदायित्व का अभाव	सामुदायिक विकास के उत्तरदायित्व के बिंदु समाहित।

HELP की भूमिका –

① समान लाइसेंस का प्रावधान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निजी निवेश को आकर्षित करेगा,

(ii) रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल सरकार को लाभ प्रदान करेगा,

(iii) लाभ / राजस्व वितरण के स्पष्ट कानूनी प्रावधान विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करेंगे।

(iv) उत्पादन वृद्धि के साथ लाभ का प्रावधान अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करेगा, जो कि आयात प्रतिस्थापन का माध्यम बनेगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Although equal land ownership rights are essential for the economic empowerment of women, these rights are often overlooked. Discuss. What steps have been taken by the government to ensure land rights for women?

यद्यपि समान भूमि स्वामित्व अधिकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हैं परन्तु इन अधिकारों की प्राय: अनदेखी की जाती रही है। चर्चा कीजिए। महिलाओं के लिए भूमि अधिकार सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारत में भू सुधार का एक प्रमुख अवयव भू-स्वामित्व में महिलाओं की अनुपस्थिति है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भू स्वामित्व का अच्छा अधिकार आवश्यक है, किंतु हम अभी भी इस दिशा में काफी पीछे हैं—

(i) परंपरागत पुरुष सत्तात्मक दृष्टिकोण

(ii) पितृस्थानिकता के वर्चस्व के कारण विवाह के बाद भू-स्वामित्व से वंचित

(iii) ~~स्वयं महिलाओं में इस बात का सामाजीकरण (घर कर चुका है कि अचल संपत्तियाँ केवल पुरुष स्वामित्व में होती हैं,~~

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परिणामतः आज भारतीय भू-रिकॉर्ड में महिला स्वामित्व का अंश दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि घर में सबसे वरिष्ठ सदस्य महिला होने के बावजूद भी कनिष्ठ पुरुष सदस्य को ही वास्तविक हकदार समझा जाता है।

सरकार द्वारा प्रयत्न -

(i) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा चल-अचल संपत्ति में समान हिस्सा,

(ii) सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुरूप, संपत्ति विवाद में महिला पक्ष भी अनिवार्य पक्षकार

(iii) भू स्वामित्व वरिष्ठतम महिला सदस्य के नाम पर अभिलेखित

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Micro irrigation methods would not only lead to increased productivity but also conservation of water. Enumerating the different methods of micro irrigation, identify the bottlenecks in their implementation and benefits that can acrue once they are implemented.

सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों से न केवल उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि जल संरक्षण भी होगा। सूक्ष्म सिंचाई की विभिन्न पद्धतियों को गिनाते हुए उनके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं एवं उनके कार्यान्वयन से प्राप्त हो सकने वाले लाभों की पहचान कीजिए।

सूक्ष्म सिंचाई More Crop, One drop के सिद्धांत के आधार पर कृषि उत्पादकता में वृद्धि का प्रभावी माध्यम सिद्ध होती है, साथ ही जल के दक्षतम उपयोग से, जल संरक्षण की दिशा में भी प्रभावी कदम होगी,

पद्धतियाँ –

① स्प्रिंकलर –

(क) इसमें स्प्रिंकलर (फव्वारे) के माध्यम से सिंचाई की जाती है।

(ख) गहन कृषि फसलों हेतु लाभकारी,

(ग) पत्तियों आदि पर जमी धूल आदि को हटाकर फोटोसिंथेसिस को भी प्रभावी,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ii) ड्रिप सिंचाई-

(क) खेत में विस्तृत ट्यूब में फसल के जड़ के समीप छिद्र द्वारा सिंचाई,

(ख) पूंजी गहन तकनीक,

(ग) जल का कुशलतम उपयोग,

प्रमुख बाधाएँ -

(i) किसानों के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव,

(ii) ये तकनीकें पूंजी गहन हैं,

(iii) जल संरक्षण के प्रति सजग दृष्टिकोण का अभाव

(iv) इसके क्रियान्वयन हेतु विद्युत, गति नियंत्रक आदि तकनीकों का अभाव,

संभावित लाभ -

(i) कम जल उपयोग से अधिकतम फसल प्राप्ति,

(ii) जल संरक्षण द्वारा संपोषणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति,

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) उत्पादकता अधिक होने से उचित लाभ की प्राप्ति,

(iv) फर्टिगेशन तकनीक को समाहित कर उत्पादन अधिक बढ़ाया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. It has been argued that the Nutrient based subsidy (NBS) scheme launched in 2010 has created more problems than it intended to solve. Examine. What measures are required to address concerns arising out of the fertilizer subsidy policy in India?

ऐसी दलीलें दी जाती रही हैं कि वर्ष 2010 में आरंभ की गई पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एन.बी.एस.) योजना ने समस्याओं के समाधान के बजाए कहीं अधिक समस्यायें उत्पन्न की हैं। परीक्षण कीजिए। भारत में उर्वरक सब्सिडी नीति से उत्पन्न चिन्ताओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जाने की आवश्यकता है?

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. The success of "Operation Flood" proves that thoughtful intervention in the livestock sector has the potential of acting as a growth engine for the agriculture sector and rural economy. In light of this, examine the potential of the livestock sector and the challenges it faces. Also enumerate the steps taken by the government in recent years to leverage the potential of this sector.

"ऑपरेशन फ्लड" की सफलता से सिद्ध होता है कि पशुधन क्षेत्रक (लाइवस्टॉक सेक्टर) के लिए उठाए जाने वाले विचारशील कदमों में कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु विकास इंजन के रूप में कार्य करने की क्षमता है। इस तथ्य के आलोक में, पशुधन क्षेत्रक की क्षमताओं एवं उसके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही, सरकार द्वारा हाल के वर्षों में इस क्षेत्रक की क्षमता का लाभ प्राप्त करने हेतु उठाए गए कदमों को गिनाइए।

ऑपरेशन फ्लड, 1960-70 के दशक में गुजरात में प्रारंभ किया गया डेयरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम था, जिसने न केवल आय को बढ़ाया बल्कि 'अमूल' जैसा सशक्त ब्रांड का निर्माण भी संभव कर दिया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसे मील का पत्थर माना जाता है।

किंतु यह आंदोलन पूरे भारत में सफल नहीं हो सका, जिससे पशुधन क्षेत्रक की वास्तविक सामर्थ्य का लाभ नहीं मिल पाया है।

पशुधन क्षेत्रक की क्षमताएँ-

① भारत सर्वाधिक पशुधन संख्या वाला

देश है।

(ii) अधिक जनसंख्या उपभोक्ता मांग का शाश्वत उदाहरण है,

(iii) दक्षिण-एशियाई राष्ट्रों में कुछ उत्पाद निर्यात की संभावना।

चुनौतियाँ-

(i) पशुधन के लिए आवश्यक चारे के प्रबंधन का अभाव।

(ii) यातायात व्यवस्था का अभाव उचित सप्लाई चेन के निर्माण में असक्षम,

(iii) उचित मार्गदर्शन व प्रोत्साहन का अभाव,

(iv) संवार्धित नस्लों का भारतीय जलवायु के अनुकूल न होना,

सरकार द्वारा उठाए गए कदम-

(i) बजट में डेयरी विकास हेतु वृहत् राशि का आवंटन,

(ii) पशु-पहचान पत्र द्वारा पशु चिकित्सा

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आदि हेतु संभावनाशील प्रयोग,
(iii) पशु नस्ल सुधार हेतु पशुधन संजीवनी बैंकों का निर्माण,

निष्कर्ष – अपार संभावना युक्त डेयरी क्षेत्रक को बढ़ावा देकर हम न केवल आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाएंगे, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण में भी समर्थ सिद्ध हो पाएँगे।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. What are the twin objectives of government food procurement policy in India? Discuss the instruments of this policy. Do you think there is an urgent need for rationalization of MSP policy in India?

भारत में सरकारी खाद्य खरीद (अधिप्राप्ति) नीति के दोहरे उद्देश्य क्या हैं? इस नीति के साधनों पर चर्चा कीजिए। क्या आप यह मानते हैं कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) नीति को तत्काल युक्तिसंगत बनाये जाने की आवश्यकता है?

किसानों से अनाज खरीदकर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आम जनता को उपलब्ध करना सरकारी खाद्य खरीद का अंग है,

दोहरा उद्देश्य -

(I) न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा किसानों को पर्याप्त आय,

(II) सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा मुद्रास्फीति से आमजन का बचाव,

नीति के साधन -

(I) सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा,

(II) बाजार खरीद मूल्य MSP से कम होने पर सरकार द्वारा खरीद

(III) बफर स्टॉक द्वारा खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना,

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iv) राज्य निर्देशित सार्वजनिक राशन दुकानों द्वारा सस्ते मूल्य पर अनाज वितरण,

MSP को युक्तिसंगत बनाने हेतु उपाय

(i) फसल बोने से पूर्व अन्तिम मूल्य की घोषणा, ताकि किसान आश्वस्त होकर जोखिम ले सके,

(ii) आपदा/अन्य कारण से फसल नष्ट हो जाने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान,

(iii) किसानों आज भी सभी 25 फसल उपजों के MSP मूल्य से परिचित नहीं हैं। अतः जागरूकता प्रसार,

(iv) बफर स्टॉक में भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जाए।

(v) राष्ट्रीय कृषि मंडी का निर्माण प्रभावी कदम साबित होगा,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Discuss the potential of Food Processing Industry with regards to employment generation in India. What are the key impediments which need to be overcome before the sector can become internationally competitive and achieve high growth?

भारत में रोजगार सृजन करने के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। वे प्रमुख बाधाएँ कौन-सी हैं जिन्हें इस क्षेत्रक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने एवं उच्च विकास प्राप्त करने हेतु दूर किए जाने की आवश्यकता है?

खाद्य फसलों को प्रसंस्कारित कर उनकी गुणवत्ता / दीर्घकालिता में वृद्धि कर उपयोगी बनाने की क्रिया खाद्य प्रसंस्करण कहलाती है।

संभावनाएँ –

(i) भण्डारण क्षमता के अभाव के कारण खाद्य उत्पाद को उनके मूल रूप में रक्षित करना प्रभावी नहीं होता है, अत: प्रसंस्करण बेहतर विकल्प है।

(ii) बढ़ती शहरी जनसंख्या के मध्य प्रसंस्करित उत्पादों की माँग।

(iii) उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास प्रसंस्कृत उद्योगों / उत्पादों को प्रेरित करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iv) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि पर पड़ते प्रच्छन्न बेरोजगारी के प्रभाव को रोककर रोजगार देने में प्रभावी सिद्ध होंगे,

बाधाएँ -

(i) खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का अभाव।

(ii) फूड पार्क योजनाओं के प्रति उद्यमी / कृषक वर्ग का सीमित झुकाव।

(iii) कृषक वर्ग में प्रसंस्करण उद्योगों के प्रति जागरूकता का अभाव।

(iv) सप्लाई चेन व्यवस्था का प्रभावी न होना।

(v) निर्यातोन्मुख इकाईयों द्वारा प्रसंस्करित उद्योगों को कम महत्व देना,

(vi) सरकार द्वारा प्रसंस्करित उद्योगों को प्रोत्साहन का अभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्टत: सरकारी प्रोत्साहन, नवोन्मेषी सोच, व जागरूक कृषक समाज का समन्वय ही प्रसंस्करण उद्योग को सफल बना पाएगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Mixed farming for the resource poor farmer is mostly a poverty induced option. Comment. What role can the government play to help farmers realise the potential from mixed farming.

संसाधनहीन निर्धन किसानों के लिए मिश्रित कृषि मुख्य रूप से निर्धनता प्रेरित विकल्प है। टिप्पणी कीजिए। मिश्रित कृषि की संभावनाओं को साकार करने हेतु, सरकार किसानों का सहयोग करने में क्या भूमिका निभा सकती है ?

कृषि की वह पद्धति जिसमें कृषि अंतरण (more than one crop in an agriculture year) के साथ पशुपालन भी किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाती है।

निर्धन किसानों हेतु लाभ-

(i) डेयरी उत्पादों का स्वउपभोग के साथ व्यापार,

(ii) पशुओं को चारे आदि के लिए कृषि अपशिष्ट का प्रयोग लागत घटाएगा,

(iii) पशुओं द्वारा खरपतवारों का आहरण कृषि-भूमि उत्पादकता को बढ़ाएगा,

(iv) चूँकि भारत में कृषि उत्पादकी

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मात्रा कम है, परिणामतः छोटे किसान मिश्रित कृषि की ओर प्रेरित होते हैं जबकि समुचित ढाँचे व ज्ञान के अभाव में इसका वास्तविक लाभ लेने में असक्षम हैं।

सरकार की भूमिका -

(i) मिश्रित कृषि के उप-उत्पादों की सप्लाई चेन को सुदृढ़ करे।

(ii) आधारभूत ढाँचा उपलब्ध कराकर निर्धन किसानों को व्यापारिक कृषि से जोड़े।

(iii) करनाल डेयरी उद्योग के समान छोटे किसानों के वैकल्पिक रोजगार हेतु सामूहिक प्रयोग किये जा सकते हैं।

(iv) प्राथमिकता क्षेत्रक ऋणों तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित किया जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(v) पशु संवर्द्धन हेतु प्रेरित किया जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. What do you understand by cropping pattern? What are the factors that influence the cropping pattern in India? Is there a need to change the cropping pattern in the country keeping the agro-ecological concerns in mind?

फसल प्रतिरूप (क्रॉपिंग पैटर्न) से आप क्या समझते हैं? भारत में फसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कृषि-पारिस्थितिकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए क्या देश में फसल प्रतिरूप को परिवर्तित करने की आवश्यकता है?

फसल उत्पादन में कालगत व स्थानगत विभिन्नता फसल पैटर्न कहलाती है।

प्रभावित करने वाले कारक-

(I) वर्षा प्रतिरूप के आधार पर फसल

(II) भूमि की उत्पादकता फसल चयन का आधार

(III) सिंचाई व्यवस्था,

(IV) व्यापारिक लाभ (जैसे महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादन)

(V) जनसंख्या घनत्व के आधार पर श्रम गहन / पूंजी गहन कृषि

(VI) सरकारी राजसहायता,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

फसल - प्रतिरूप की वर्तमान आवश्यकता

(i) पंजाब जैसे जल-अनुपलब्धता वाले क्षेत्रों में जल गहन कृषि,
(ii) महाराष्ट्र के जल अभाव क्षेत्रों में गन्ना कृषि
(iii) दाल उत्पादन की पर्याप्त संभावना के बावजूद निष्क्रियता

ये उदाहरण सिद्ध करते है कि फसल पैटर्न पर पुनर्विचार आवश्यक है, जिसके लिए

(i) जल की उपलब्धता (ii) भूमि उत्पादकता (iii) उत्पादन की मात्रा

को ध्यान में रखकर ऐसी समर्थनकारी नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि सर्वश्रेष्ठ व संपोषणीय मॉडल उभरकर आए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)